20-11-13 हिन्दुस्तान

नगर निकाय-पंचायती राज कानून में होगा संशोधन

घर में शौचालय नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

घर में शौचालय नहीं बनाया तो भविष्य में नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। घरों में शौचालय निर्माण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण स्वच्छता वाली पंचायतों व प्रखंडों के लिए प्रोत्साहन का भी एलान किया। साथ ही वर्ष 2020 तक बिहार के हरेक घर में शौचालय निर्माण कराने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 तक बिहार में शौचालयविहीन आधे घरों में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य था। हम चाहते हैं कि 2020 तक सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो जाए। मानव विकास मिशन के तहत इस कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह अभियान ही नहीं, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। यही वजह है कि हमने तय किया है कि जिनके परिवार में शौचालय नहीं होगा, वह नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत से गरीब उम्मीदवार हैं, वह कह सकते हैं कि हम कहां से बनाएंगे। हम ऐसे लोगों से पूछेंगे कि सरकार पैसे देने को तैयार है, तब दिक्कत क्यों हो रही है?

● प्रोत्साहन पुरस्कार : पेज-02

विश्व शौचालय दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा

पटना में मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा।

पंचायतों में बनेगा ब्रिज फंड

इंदिरा आवासों में शौचालय का निर्माण कराने के लिए हरेक पंचायत में ब्रिज फंड की स्थापना की जाएगी। सभी पंचायत में दो-दो लाख रुपये रखे जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों को पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाभार्थियों को इस कोष से धन दे दिया जाएगा। बाद में जब निर्मल भारत अभियान से राशि मिलेगी तो उसे ब्रिज फंड में जमा कर दिया जाएगा। इस तरह साल दर साल शौचालय के निर्माण में आसानी होगी।

बीडीओ बनवाएंगे शौचालय

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्मल भारत अभियान और मनरेगा के समन्वित कार्यक्रम में इन्दिरा आवासों में शौचालय का निर्माण इस योजना के साथ-साथ बीडीओ द्वारा भी कराया जाएगा। अन्य सभी लाभान्वितों के घरों में शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायतें कराएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने जनगणना के आधार पर बिहार में 1.11 करोड़ ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे पारिवारिक सर्वेक्षण में 2.19 करोड़ शौचालयविहीन घर मिले हैं। हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि बिहार के सभी शौचालयविहीन घरों में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी सेवकों और समर्थ लोगों से भी तीन माह के अपने घरों में शौचालय का निर्माण करा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, सचिव अमृत लाल मीणा व पीएचईडी के अभियंता प्रमुख जयशंकर चौधरी ने भी संबोधित किया।

2 Page